

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3465

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सहायता

3465. श्री लुम्बा राम:  
श्री दिलीप शङ्कीया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में वर्तमान में चल रहे स्टार्टअप्स की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार राजस्थान के जालौर सिरोही सहित देश के युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में स्टार्टअप्स द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है;
- (ङ) क्या स्टार्टअप्स आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्यों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान कर रहे हैं; और
- (च) यदि हां, तो उत्तर पूर्वी राज्यों और राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सुदृढ़ ईकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत उल्लिखित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 1,52,139 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य (यूटी) क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

(ख) और (ग) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए तथा राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में स्टार्टअप स्थापित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार निरंतर विभिन्न प्रयास कर रही है।

प्रमुख स्कीमों, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार तक पहुंच में सुधार लाने और स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करके सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने के लिए पहलें की गई हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर), संसाधनों तक आसान पहुंच और स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहयोग प्राप्त करने को संभव बनाते हैं। विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य प्रयास और कार्यक्रम इन उपायों के लिए पूरक सिद्ध होते हैं।

इसके अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा युवा-केंद्रित पहलों की शुरुआत की गई है, जैसे मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना, जिसका उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपीएस), स्वयंसेवा के अवसरों, परामर्श कार्यक्रम इत्यादि के माध्यम से युवा विकास और युवा-नेतृत्व आधारित विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक व्यवस्थागत तंत्र प्रदान करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईआईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए देश भर में कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

भारत सरकार के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में 5,395 कंपनियों को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, विशेष रूप से जालौर जिले से 12 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और सिरोही जिले से 35 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

**(घ) से (च) :** सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कुल 1,52,139 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियां, रोजगार सृजन और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं तथा इनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि इन्होंने 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान राज्य की कंपनियों सहित स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों द्वारा (स्व-सूचित) सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-I

**दिनांक 17.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 3465 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या
-------------------------	---

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	68
आंध्र प्रदेश	2,446
अरुणाचल प्रदेश	44
असम	1,434
बिहार	3,054
चंडीगढ़	521
छत्तीसगढ़	1,679
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	60
दिल्ली	15,645
गोवा	562
गुजरात	12,540
हरियाणा	7,961
हिमाचल प्रदेश	543
जम्मू और कश्मीर	942
झारखण्ड	1,425
कर्नाटक	16,093
केरल	6,173
लद्दाख	18
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	4,913
महाराष्ट्र	27,014
मणिपुर	164
मेघालय	58
मिजोरम	40
नागालैंड	80
ओडिशा	2,670
पुदुच्चेरी	160
पंजाब	1,672
राजस्थान	5,395
सिक्किम	11
तमिलनाडु	10,053
तेलंगाना	7,918
त्रिपुरा	133
उत्तर प्रदेश	14,429
उत्तराखण्ड	1,217
पश्चिम बंगाल	5,001
<b>कुल</b>	<b>1,52,139</b>

\*\*\*\*\*



अनुबंध-II

दिनांक 17.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 3465 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों द्वारा 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों (स्व-सूचित) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों (स्व-सूचित) की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	567
आंध्र प्रदेश	23,125
अरुणाचल प्रदेश	535
असम	13,460
बिहार	28,848
चंडीगढ़	5,430
छत्तीसगढ़	16,016
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	694
दिल्ली	178,798
गोवा	4,256
गुजरात	150,065
हरियाणा	103,026
हिमाचल प्रदेश	4,271
जम्मू और कश्मीर	7,769
झारखण्ड	12,590
कर्नाटक	186,352
केरल	54,420
लद्दाख	139
लक्षद्वीप	38
मध्य प्रदेश	50,887
महाराष्ट्र	304,078
मणिपुर	1,476
मेघालय	442
मिजोरम	332
नागालैंड	4,157
ओडिशा	32,360
पुदुच्चेरी	1,664
पंजाब	18,776
राजस्थान	55,229
सिक्किम	73
तमिलनाडु	106,768
तेलंगाना	89,173
त्रिपुरा	1,809
उत्तर प्रदेश	148,677

उत्तराखण्ड	10,539
पश्चिम बंगाल	50,680
कुल	<b>16,67,519</b>

\*\*\*\*\*